(च) क्या सरकार ने हथकरघा को कम उत्पादकता वाले राज्यों की पहचान की है, यदि हां तो वे कौन-कौन से राज्य हैं और आगामी वर्षों के दौरान उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार की योजना क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां,

(ख) जी हां,

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिल्ली और असम में प्रति करघा, प्रति दिन क्रमशः 14.28 मीटर और 0.63 मीटर कपड़े का उत्पादन होता है ।

(ङ) और (च) उत्तर पूर्वी राज्यों, विशेषकर असम में घरेलू हथकरघों की संख्या अधिक है । इन राज्यों में बुनाई एक पारिवारिक और सांस्कृतिक कार्य-कलाप है और बुनकरों की समूची आय में वृद्धि करने का एक साधन है । करघे की उत्पादकता, कपड़े के प्रकार, करघे के प्रकार, बुनकर की क्षमता आदि पर निर्भर करता है। संशोधित उपकरणों की आपूर्ति के माध्यम से हथकरघों की उत्पादकता में वृद्धि करने और कपड़े की क्वालिटी में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने आधुनिकीकरण की एक योजना कार्यान्वित की है । 8वीं योजना के दौरान करघों के आधुनिकीकरण के लिए 17 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित किया गया है। हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने और अच्छी किस्म का कपड़ा तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 1987 से बुनकरों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं । वर्ष 1991–92 में आरम्भ की गई प्रोजेक्ट पैकेज योजना का उद्देश्य भी बुनकरों की आय में वृद्धि करना है।

बिजली–चालित करघा मजदूरों को प्रोत्साहन

2607. **श्री वीरेन जे० शाह :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 अक्तूबर 1992 के "ट्रिब्यून" में "गवर्नमेंट स्कीम टु एनश्योर पावरलूम वर्कर्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ।

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में कपड़े की आवश्यकता का 65 प्रतिशत से अधिक भाग बिजली-चालित करघों द्वारा पूरा किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो बिजली–चालित करघा मजदूरों की हालत और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए उनको क्या-क्या प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण बिजली-चालित करघों की स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1992–93 के दौरान इस क्षेत्र में उत्पादन क्षमता कितनी रही है और इस अवधि के दौरान उनकी क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता कितनी रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत : (क) जी हां।

(ख) जी हां । वर्ष 1991–92 के दौरान मिल करघा क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन कुल उत्पादन का 71 प्रतिशत था ।

(ग) सरकार ने वर्ष 1992–93 के दौरान जीवन बीमा निगम के सहयोग से विद्युतकरघा बुनकरों के लिए एक समूह बीमा योजना शुरू की है। इस योजना में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा विद्युतकरघा क्षेत्र द्वारा वार्षिक प्रीमियम की बराबर भागीदारी करने की व्यवस्था है। 10,000 रु० वाले बीमा के लिए 120 रु० का वार्षिक प्रीमियम अदा किया जाएगा। भारत सरकार की निधियों के अंशदान को प्रतिपूर्ति आधार पर राज्य सरकार के जरिए सरणीबद्ध किया जाएगा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) इस समय 11.9 लाख विद्युत-करघा पंजीकृत हैं जिनकी क्षमता लगभग 24,000 मिलियन वर्ग मीटर कपड़ा प्रतिवर्ष है तथा जिनका प्रतिशत उपयोग 67 प्रतिशत बनता है।

Export of Cotton

2608. SHRIMATI MIRA DAS :

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH :

SHRI P. UPENDRA :

SHRI MUHAMMAD MASOOD KHAN :

SHRI CHIMANBHAI MEHTA :

Will the Minister of TEXTILES be please to state :

(a) whether it is a fact that carry-over stock of the cotton is likely to be more than 47 lakh bales of cotton at the end of the year;

(b) if so, what are the reasons for which only 5 lakh tonnes of bales have been permitted for exports and not 15 lakh bales at present;

(c) whether Government propose to ask institutional buyers to purchase about 40 per cent of the current year production i.e., around 30 lakh bales to prevent slump in the market and protect farmers' interest; and

(d) whether cotton production in the world is higher than consumption ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT) : (a) No Sir. Cotton Advisory Board (CAB), in its meeting held on 9th October, 1992, has estimated the carry-over stock of cotton at the end of the cotton year 1992-93 at 37.70—42.70 lakh bales.

(b) After evaluating the cotton scenario and in terms of Governments long term strategy regarding export of cotton to help cotton farmers, the Government has pleased 9.26 lakh bales of cotton so far during the current cotton season.

(c) Cotton Corporation of India (CCI) is an organisation which undertakes price support operations on behalf of the Government, as and when the kapas prices fall below the minimum support price levels fixed. CCI's endeavour is to sustain the price level of Kapas. In addition, CCI also undertakes commercial operations in cotton for domestic & export requirements. To protect the farmers' interest, the Government have already released a quota of 9.26 lakh bales for export during the year to CCI and the other Coop. Institutions.

(d) No, Sir. The Cotton production in the world during 1992-93 has been projected at 18.90 million metric tonnes as against the estimated consumption of 19.04 million metric tonnes.

Modernisation of Sick Textile Mills

2609. SHRI SURESH PACHOURI : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that under the new textile policy Government had earmarked 800 crore rupees for the modernisation of sick textile Mills in the country in 1987;

(b) whether it is also a fact that only fifty per cent amount has been spent so far;

(c) if so, what are the details of amount spent year-wise since 1987 and the reasons for not spending the entire funds earmarked for the purpose; and